

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-2269/2014

नारायण लाल शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, भरतपुर।
3. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, बयाना, भरतपुर।
4. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भरतपुर।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 10.10.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखवीर सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्था विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.08.1985 को अध्यापक ग्रेड-III के पद पर हुई थी। इसके पश्चात पंचायती राज विभाग ने नोटिफिकेशन दिनांक 06.08.1988 व 11.08.1989 के द्वारा यह तय किया कि जिन अध्यापकों की नियुक्ति अस्थाई रूप से वर्ष 1988 से पूर्व हुई है, उनकी सेवाएं स्क्रीनिंग के बाद नियमित की जायें। इसके पश्चात अपीलार्थी की सेवाएं सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.08.2012 से दिया जाना चाहिए था, परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्था विभाग को कई बार अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की है एवं साथ ही ब्याज दिये जाने की प्रार्थना भी की है।
2. प्रत्यर्था विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति विकास अधिकारी बयाना के आदेश दिनांक 01.08.1985 के द्वारा तदर्थ आधार पर 6 माह के लिए अथवा चयनित अभ्यर्था उपलब्ध होने तक के लिए की गई। तत्पश्चात् दिनांक 17.05.1986 के द्वारा

उसे कार्यमुक्त भी कर दिया गया तथा पुनः विकास अधिकारी बयाना के आदेश से 28.06.1986 के द्वारा तदर्थ तौर पर छः माह के लिए नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 17.05.1989 के द्वारा अपीलार्थी को नियमित किया गया माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 3620/2009, 2848/2006 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम् जगदीश नारायण चतुर्वेदी मे पारित विनिश्चय के अनुसार अपीलार्थी नियमित नियुक्ति 17.05.1989 से ही चयनित वेतनमान सहित सेवा संबधित समस्त लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है। अपीलार्थी विधि अनुसार देय परिलाभ स्वीकार एवं अंगीकार करता आ रहा है और बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए लम्बे बिलम्ब बाद बिना और बिलम्ब क्षम्य की प्रार्थना के बिना ही सारहीन एवं निरर्थक तथ्यों के आधार पर माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। विभागीय विधि अनुरूप नियमितकरण आदेश दिनांक 17.05.1989 और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Rajasthan Vs-Jagdish Narain Chaturvedi : (2009)12 SCC 49 पारित विनिश्चय की रोशनी मे प्रार्थी नियमित नियुक्ति तिथी से ही सेवा संबधित लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होने से उक्त अपील काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 17.05.1989 के द्वारा नियमित की गई है इसलिए State of Rajasthan Vs- Jagdish Narain Chaturvedi : (2009) 12 SCC 49 held ad hoc employees entitled for selection scale from the date of their regular appointment. अनुसार प्रार्थी नियमित होने की तिथी 17.05.1989 से ही सेवा संबधित परिलाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है इसलिए अपील अपीलार्थी काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया।
4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थाई रूप से दिनांक 01.08.1985 को हुई थी और बाद में स्क्रीनिंग के पश्चात अपीलार्थी की सेवाएं नियमित की गई है। अपीलार्थी ने अपनी इस अपील में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसकी सेवाएं किस दिनांक को नियमित की गई थी। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 17.05.1989 को नियमित किया जाना बताया है। इस अपील में अपीलार्थी ने प्रथम नियुक्ति की दिनांक 01.08.1985 से सेवाओं की गणना करते हुए तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी की जो प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.08.1985 को हुई थी, वह नियमित नियुक्ति नहीं थी, बल्कि तदर्थ आधार पर नियुक्ति थी। अपीलार्थी के

नियुक्ति आदेश अनुलग्नक-1 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियुक्ति 6 माह के लिए अथवा चयनित प्रत्याशी प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्ति दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of

seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

5. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में यह माना गया है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवा नियमित मानी जाएगी। अपीलार्थी की जो सेवाएं दिनांक 17.05.1989 को स्क्रीनिंग के पश्चात नियमित की गई है, उसके पूर्व की सेवाएं अपीलार्थी ने तदर्थ (ad-hoc) आधार पर दी थी, जो सेवाएं अपीलार्थी चयनित वेतनमान के लाभ के लिए अपनी सेवा में नहीं जुड़वा सकता है।
6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि अपीलार्थी की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से की जाकर अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ दिलाया जाए। परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)